

एक अप्रैल को मनाया जाएगा उड़ीसा दिवस

हर राज्य का स्थापना दिवस मनाएगी भाजपा सरकार: रेखा

हरिभूमि न्यूज ॥ नई दिल्ली

दिल्ली में हर राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि हर राज्य का स्थापना दिवस राष्ट्रीय राजधानी में मनाया जाएगा, क्योंकि यहां सभी राज्यों के लोग रहते हैं। सभी राज्यों के लोग दिल्ली को अपना मानते हैं, ऐसे में उनकी भावनाओं को देखते हुए इस बारे में फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। गौरतलब है कि देश में 28 पूर्ण राज्य हैं और दिल्ली सहित आठ संघ राज्य क्षेत्र हैं। यानी



कुल मिलाकर 36 बैठते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। भारत के बड़े से लेकर छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जनसांख्यिकीय, इतिहास और संस्कृति, वेश-भूषा, त्यौहार, भाषा आदि विभिन्न हैं। अभी तक दिल्ली अपना भी स्थापना

दिवस नहीं मनाती थी। दिल्ली भी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। दिल्ली देश की राजधानी भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे में दिल्ली राज्य के गठन की तारीख को ही स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली में देश की राजधानी 114 पहले 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाए जाने की

घोषणा की थी। 12 दिसंबर, 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, 13 फरवरी, 1931 को भारत के वायसराय लार्ड इरविन ने दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया था।

ऐसी किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना हो : विजेंद्र

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा अध्यक्ष ने नेता विपक्ष के आरोपों पर सदन में व्यवस्था देते हुए कहा कि मैं ऐसी किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना हो और मीडिया में अपने आपको महिमामंडित करने के लिए सदन का समय बर्बाद करना हो। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए विशेष उल्लेख के नोटिस को अनुमति नहीं देने के बारे में मेरे फैसले के संबंध में मुझे नेता विपक्ष आतिथी का एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि सदन के सदस्यों को केवल उन विषयों पर प्रश्न पूछने चाहिए या चर्चा करनी चाहिए जिनका मंत्री उत्तर दे सकत हैं। या उन पर कोई कार्यवाई कर सकते हैं। हालांकि सदन में उठाए जाने वाले मामले के विषय को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष आरक्षित विषयों पर भी नोटिस की अनुमति केवल तब दे सकते हैं जब उन्हें लगता है कि यह दिल्ली के लोगों को प्रभावित करने वाला बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण मामला है और जिस पर सदन को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विपक्ष के जिन नोटिसों को मैंने स्वीकार नहीं किया था वे महज सदन की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और सदन में संगठित व्यवधान पैदा करने का प्रयास थे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विशेष उल्लेख के तहत उठाए जाने वाले मामले तत्काल सार्वजनिक महत्व के विषयों से सम्बन्धित होते हैं। मैंने देखा है कि विपक्ष के सदस्य जनता के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय व्यवधान पैदा करने में अधिक रुचि रखते हैं।



नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधरपतिवार को घोषणा की कि नवरात्रि से पहले 'अवेध' मीट विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक करनैल सिंह ने नवरात्रि से पहले फुटपाथों और दुकानों पर खुलेआम मीट बेचे जाने को लेकर चिंता व्यक्त की। वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं कोई कोई अवैध रूप से बैठा है तो उसे हटया जाना चाहिए। उन्होंने विधायकों से अपने-अपने क्षेत्र में किसी भी तरह के अतिक्रमण की जानकारी देने को कहा और आश्वासन दिया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाई की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करूंगा। वर्मा ने सदन को बताया कि राजधानी में मांस और मछली बेचने वाली अवैध इकाइयों को हटाने के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं।

मंत्री द्वारा 'माई' बोलने पर विपक्ष का सदन में हंगामा, दो सदस्यों को किया बाहर

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने माई का संबोधन करने पर विपक्ष भड़क गया और सदन में हंगामा करने लगा। सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से न चलने देने पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष के सदस्य कुलदीप कुमार और विशेष रवि को मांशलों द्वारा सदन से बाहर करा दिया। गौरतलब है कि मंत्री प्रवेश वर्मा एक सवाल के जवाब में विपक्ष को माई कहा। इस पर विपक्ष की नेता आतिथी ने आरोप लगाया कि मंत्री उनके लिए अमर्यादित शब्दों को इस्तेमाल किया है। इस अवय विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैंने कहा कि माई इतनी बदतमीजी कहां से लाते हो। जिस पर आप विधायक भड़क उठे और हंगामा जारी रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने मारी हंगामा करने पर विपक्षी सदस्य कुलदीप कुमार और विशेष रवि को मांशलों द्वारा सदन से बाहर करा दिया। इसके बाद सदन में छठ पूजा के सवाल पर पक्ष विपक्ष में जमकर शोर हुआ। इस बीच मंत्री कपिल मिश्रा भी खड़े हो गए और कहने लगे कि 'शर्म आनी चाहिए जो छठ पूजा के सवाल को रोका जा रहा है। वहीं विपक्ष के सदस्य विशेष रवि ने करोल बाग के बाजारों में ट्रैक छोटा करने के लिए 30 अक्टूबर 2024 को लिखे गए अपने पत्र पर कार्यवाई का जवाब मांगा। इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि वर्ष 2018-19 में गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस क्षेत्र को पैदल यात्रियों के लिए नियत कर दिया गया था तथा मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और डीएमआरसी की मार्गदर्शी से ट्रैक (फुटपाथ) चौड़ाकरण का काम किया गया था। फिलहाल ट्रैक को छोटा करने की कोई योजना नहीं है। वहीं सत्तापक्ष के सदस्य रवि नेगी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क के किनारे एमसीडी की पार्किंग का मुद्दा उठाया।

छठी-सातवीं विधानसभा की समितियों में लंबित मामले होंगे खत्म, सदन में प्रस्ताव पास

नई दिल्ली। छठी और सातवीं विधानसभा की विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति में लंबित मामलों पर मुख्य सचेतक अमरा वर्मा की ओर से एक प्रस्ताव सदन में पेश किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि लंबित मामलों पर आगे कोई कार्यवाई नहीं की जाए तथा उन्हें निपटारा हुआ माना जाए। इस प्रस्ताव को सदन की सहमति से पारित कर दिया गया। इस संबंध में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन में कहा कि 04 दिसंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, सातवीं विधानसभा में तीन प्रस्ताव पारित किए गए थे कि विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अधूरे कार्यों की जांच नियम-183 के तहत आठवीं विधानसभा की संबंधित समितियों द्वारा की जाए। नियम-183 के तहत, विधानसभा के भंग होने से पहले किसी भी समिति के अधूरे कार्य को नई विधानसभा की समिति को भेजा जा सकता है। छठी और सातवीं विधानसभा के भंग होने के समय विधानसभा ने इन तीनों समितियों के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया था। मैंने समिति के समक्ष लंबित सभी मामलों की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन मामलों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था। छठी विधानसभा के 59 मामले और सातवीं विधानसभा के 69 मामले विशेषाधिकार समिति द्वारा लंबित रखे गए थे।

विधायकों की वेतन वृद्धि जनविरोधी, आप-भाजपा की मिलीभगत : यादव

नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस ने विधायकों की वेतन वृद्धि को जनविरोधी बताते हुए कि इससे साफ हो गया है कि जनहित की अनेकसी करने वाली आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों की मिलीभगत है। यादव ने मांग की है कि भाजपा की दिल्ली सरकार का विधायकों के वेतन वृद्धि का निर्णय जनता के साथ अन्यायपूर्ण है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। भाजपा जनहित योजनाओं का बजट घटाकर विधायकों का वेतन बढ़ाने जा रही है। रेखा सरकार ने शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि एवं ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण जैसी आवश्यक योजनाओं के बजट में कटौती की है। जबकि 2023 में दिल्ली के विधायकों के वेतन में 66 प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है। यादव ने कहा कि विधायकों के वेतन वृद्धि फरवरी 2023 में पहले ही 66 प्रतिशत हो चुकी है। उस समय वेतन 54,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। इसके अलावा, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ व्हिप और नेता प्रतिपक्ष का वेतन 72,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 70 हजार रुपये कर दिया गया था। इसके बावजूद, अब फिर से विधायकों के वेतन में वृद्धि की मांग करना पूरी तरह गैर-जरूरी और जनविरोधी है। यादव ने कहा कि वेतन में वृद्धि के अलावा, विधायकों ने अपने स्टैफ की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है, जबकि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

बिजली की मांग का ग्राफ बढ़कर 4300 मेगावाट पार

नई दिल्ली। राजधानी में मौसम के बदलते रूप के चलते गत करीब एक सप्ताह से बिजली की मांग में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। पांच दिन के आंकड़ों का आकलन करे तो इस दौरान लगभग 663 मेगावाट बिजली की मांग बढ़ चुकी है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर दिल्ली (एसएलडीसी) पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार जहां 23 मार्च 2024 को बिजली की मांग 3683 मेगावाट थी। वह 27 मार्च 2025 को बढ़कर 4346 मेगावाट पहुंच गई। प्रतिदिन की बात करें तो 23 मार्च 2024 को बिजली की मांग 3683 मेगावाट, 24 मार्च को 4070 मेगावाट , 25 मार्च को 4099 मेगावाट, 26 मार्च को 42 85 मेगावाट और 27 मार्च 2025 को मांग का ग्राफ बढ़कर 4346 मेगावाट पहुंच गया। बिजली की बढ़ती मांग पर निजी बिजली आपूर्ति कंपनियों बीएसईएस और टाटा पावर डीडीएल का कहना है कि गर्मियों का सीजन शुरू होने की वजह से लगातार बढ़ रही है। कंपनियों का कहना है कि अभी तो मांग शुरुआती बढ़त में है। अनुमान के अनुसार मई के अंत या जून में यह मांग बढ़कर 8 हजार मेगावाट के करीब होगी। वहीं जुलाई महीने में इस बार बिजली की मांग 9 हजार मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। क्योंकि 2024 में जुलाई महीने में बिजली की मांग न खपत का नया इतिहास बनाते हुए बिजली की पीक डिमांड 8656 मेगावाट तक पहुंच गई थी। दोनों कंपनियों का दावा है कि हमने अपने अपने स्तर पर बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, निबाध बिजली आपूर्ति जारी रहेगी।

नशा मुक्त जीवन नायाब जीवन



नशे के खिलाफ, हर हरियाणवी एक साथ

नशा हमारी युवा पीढ़ी और समाज को कमजोर करता है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए 'नशा मुक्त जीवन बकेट चैलेंज' में भाग लें और नशे के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। जैसे गंदे पानी को बाहर फेंक कर हम घर को साफ करते हैं वैसे ही नशे को जीवन से बाहर फेंक कर हमें समाज को साफ-सुथरा करना है। इस टास्क को रिकॉर्ड करें और इसे सोशल मीडिया पर साझा करें। आइए, मिलकर नशा मुक्त और स्वस्थ हरियाणा बनाने का संकल्प लें।

- नायब सिंह सैनी

Hashtag #NashaMuktJeevan #NayaabJeevan

लगाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें।

आइए

नशे के खिलाफ इस यात्रा को जारी रखें

नशा मुक्त हरियाणा



सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हरियाणा के Whatsapp चैनल से जुड़ने के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें



सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा

www.pharyana.gov.in

Follow us on

@diprharyana

बोलने का मौका न मिलने पर नाराज विपक्ष की लोकसभा अध्यक्ष के दरबार में हाजिरी

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका न दिए जाने के मामले पर उखड़े विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को शून्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए हस्ताक्षर के साथ एक पत्र भी सौंपा। सदन में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोर्गोई ने बताया कि हमारे प्रतिनिधिमंडल में भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन (ईडिया) के घटक दलों में शुमार कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल, आईयूएमएल, आरएलपी और केरल के सांसद शामिल थे।



खबर संक्षेप

ऑडिशा विधानसभा में बवाल, कुर्सियां फेंकीं

भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर जांच कमिटी बनाने की मांग और कांग्रेस विधायकों के सदन से निर्लंबित किए जाने को लेकर हो रहा यह विरोध प्रदर्शन अचानक झड़प में बदल गया। रोड़ पर पड़ी कुर्सियों को पुलिसवालों पर फेंका।

एक्ट्रेस रन्या को झटका नहीं दी गई जमानत

बेंगलुरू। गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में जेल में बंद कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव को बड़ा झटका लगा है। 64वें सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले आर्थिक अपराधों के लिए स्पेशल कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को ठुकरा दिया था। निचली अदालतों से राहत न मिलने के बाद अब उनके पास केवल हाईकोर्ट का विकल्प बचा है, रन्या का कानूनी दल जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है।

तमिलनाडु : वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया था। सीएम स्टालिन ने आरोप लगाया है कि इस बिल के कारण मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो रही हैं।

पीएचडी छात्रा की मौत प्रोफेसर पर केस दर्ज

नई दिल्ली। पुलिस ने आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर के खिलाफ लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह मामला पिछले साल नवंबर में गुजरात के लोथल नामक पुरातात्विक स्थल के पास खुदाई के दौरान महिला पीएचडी छात्रा की मौत के संबंध में दर्ज किया गया है।

कॉमेडियन कामरा पर भड़के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री

अब कुणाल को प्रसाद देने का वक्त आ गया और पानी सिर के ऊपर चला गया

मंत्री शंभूराज देसाई बोले- आपतिजनक शब्दों पर मिले सजा

एजेसी ►► मुंबई

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के कॉमेडी वीडियो को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर मुख्यमंत्री व मंत्री के बयान सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कामरा पर कार्रवाई की बात कही तो अब शिंदे गुट के मंत्री शंभूराज देसाई ने कैमरे पर ही कुणाल कामरा को पीटने की बात कह दी है। बीते दिनों कामरा ने निर्मला सीतारमण पर भी एक कॉमेडी वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो को देखकर देसाई भड़क उठे हैं और कहा कि कामरा ने मर्यादा लांघ दी है। पानी सिर से ऊपर चला गया है। अब उसे प्रसाद(पीटने) देने का समय आ गया है।

राहुल गांधी से जुड़ा है मामला, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप विपक्षी दलों ने जताई नाराजगी, सभी दल रहे शामिल

सदन में शालीनता के साथ करें आचरण: बिरला

गौरतलब है कि पिछले बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन के भीतर उसकी गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए शालीनता के साथ आचरण करने की नसीहत दी थी और उसके तुरंत बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। अध्यक्ष के बयान के तुरंत बाद राहुल भी अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई को स्थगित करने की वजह से उन्हें यह मौका नहीं मिला। पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था कि मुझे लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। सदन की कार्रवाई गैर-लोकतांत्रिक ढंग से चलाई जा रही है। जिसमें सत्ता पक्ष की ही प्रधानता देखने को मिल रही है।

सत्ता पक्ष करता नियमों का उल्लंघन

गौरव ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से हुई मुलाकात में विपक्ष के नेताओं ने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की कि सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा लोकसभा प्रक्रिया से जुड़े हुए नियम-कायदों और परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अब लोकसभा अध्यक्ष के 26 मार्च को सदन में नेता प्रतिपक्ष को लेकर बिस गैप बयान का भाजपा का आईटी सेल राजनीतिकरण कर रहा है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने जिस नियम-349 का हवाला देते हुए राहुल गांधी के संदर्भ में टिप्पणी की थी। उसे लेकर अभी तक यह साफ नहीं है कि किस बात को लेकर उन्होंने ऐसा कहा था।

लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली?

लोकसभा अध्यक्ष से अपनी मुलाकात में विपक्षी सांसदों ने लंबे समय से सदन में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति न किए जाने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही कहा कि 2019 से यह पद रिक्त क्यों है? जबकि संविधान का अनुच्छेद 93 इस महत्वपूर्ण नियुक्ति की प्रावधान करता है। पिछले सप्ताह सदन में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंम-2025 के आयोजन को लेकर सदन में दिए गए वक्तव्य को लेकर भी विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से हुई अपनी मुलाकात में नाराजगी के साथ अपनी चिंता जताई और कहा कि यह संसदीय नियम-कायदों का मजाक है।

तीन दिनों तक होगा 750 जिलाध्यक्षों के साथ मंथन

जिलाध्यक्षों से कांग्रेस नेतृत्व का सीधा संवाद संगठन को नीचे से दुरुस्त करने की कवायद

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

देशभर में कांग्रेस पार्टी में प्राण फूंकने, काडरों को उत्साहित करने और निचले पायदान पर मेहनत करने वाले नेताओं, कार्यकर्ताओं को सीधे शीर्ष नेतृत्व से मुखातिब होने का अवसर देकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई शुरुआत की है। नव निर्मित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में देश भर के जिला कांग्रेस कमिटी अध्यक्षों के साथ तीन दिनों तक चलने वाले सांगठनिक मंथन में पार्टी के शीर्षस्थ नेता रूबरू हुए।



बयानबाजी बंद कर संगठन को करें मजबूत

इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2025 कांग्रेस के लिए संगठन सशक्तिकरण का वर्ष होगा। पार्टी को बुध स्तर से लेकर शीर्ष तक मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने उदयपुर घितन शिविर (2022) में लिए गए निर्णयों को पूरी तरह लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें जिला इकाइयों को सशक्त करना और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना शामिल है। खड़गे ने कहा कि जिला कांग्रेस कमिटीयां अब पार्टी का केंद्रीय बिंदु होंगी। उन्हें उम्मीदवार चयन, स्थानीय मुद्दों को उठाने, और संगठन को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका दी जाएगी। उन्होंने जिलाध्यक्षों से जवाबदेही लेने और परिणाम देने की अपील की, ताकि पार्टी का आधार मजबूत हो सके। हाल की हार (हरियाणा और महाराष्ट्र) का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि पार्टी को पुराने तरीकों से सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने माइक्रो-कम्युनिकेशन रणनीति को बेहतर करने और विपक्षी प्रचार का जवाब देने के नए तरीके खोजने की बात कही। उन्होंने कहा, हमें अपनी कमियों को दूर करना होगा और आत्मविश्वास के साथ कठिन निर्णय लेने होंगे।

कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे, जिलाध्यक्षों की बड़ी होगी भूमिका: राहुल

राहुल गांधी ने लंबे समय से चली आ रही अपनी सुधारवादी सोच को दोहराया, जिसमें फैसले लेने की प्रक्रिया को केंद्रीय स्तर से हटाकर जिला स्तर तक ले जाना शामिल है। उन्होंने कहा, जिलाध्यक्षों को टिकट वितरण और मुद्दों के चयन में निर्णायक भूमिका मिलनी चाहिए। यह पार्टी की जड़ों को मजबूत करने का तरीका है। राहुल ने जिलाध्यक्षों से उनकी राय मांगी और स्थानीय इकाइयों को मजबूत करने के तरीकों पर सुझाव लिए। उनका मानना ​​है कि जिला नेताओं की प्रतिक्रिया से ही राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कहानी तैयार होगी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हाईकमान को जिला इकाइयों से सीधे बात सुनने को

मिले। यह प्रक्रिया अब व्यवस्थित होगी, उन्होंने कहा। राहुल ने खड़गे के अनुशासन और एकजुटता के आह्वान का समर्थन किया। एक हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा, खड़गे जी ने चाबुक चलाया है, जिससे बैठक में सकारात्मक माहौल बना। उन्होंने मतदाता सूची की जांच, प्रचार के नए तरीके, और सूचना के प्रसार पर ध्यान देने को कहा। राहुल ने संकेत दिया कि पार्टी में बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे को छोड़कर नई सोच अपनानी होगी और नेताओं की क्षमता की जाँच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में खड़गे और राहुल गांधी के अलावा एआईसीसी महासचिव, राज्य प्रभारियों की मौजूदगी रही।

मुद्दों पर भाजपा को घेरें

खड़गे ने पार्टी नेताओं से एकजुट रहने और आपसी मतभेदों को सार्वजनिक न करने की अपील की। उन्होंने कहा, जब तक हम एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं करेंगे, हम अपने विरोधियों को राजनीतिक रूप से कैसे हरा सकते हैं? उन्होंने अनुशासन को पार्टी की ताकत बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, और जाति जनगणना जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे देश में जल रहे हैं और कांग्रेस को इन्हें अपनी ताकत बनाना होगा।

कांग्रेस और टीएमसी ने उठाया हाईकोर्ट के जज के घर पर मिली नकदी का मुद्दा

लोकसभा में कालेधन के मामले में ईडी की भाजपा को क्लीन चिट पर कांग्रेस का हंगामा, किए सवाल

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली



गई है। कांग्रेस नेता के बयान के तुरंत बाद पार्टी के तमाम सांसदों ने स्पीकर के आसन के समीप आकर हंगामा किया। इस दौरान वह बीजेपी शेम-शेम, तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, ईडी-बीजेपी भाई-भाई, ईडी का दुरुपयोग बंद करो के नारे लगा रहे थे। कुछ देर के हंगामे के बाद कांग्रेस के सांसद सदन से बाहर चले गए।

जज के घर मिली नकदी का नूतन मंत्री बयान दें

वहीं, शून्यकाल में ही कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और तुणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने सदन में दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर मिली नकदी का मामला उठाते हुए का नूतन मंत्री से लोकसभा में एक विस्तृत बयान देने की मांग की। मनीष ने कहा कि संसद की जिम्मेदारी बनती है कि वह न्यायपालिका से जुड़े किसी मामले की निगरानी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर जांच बिठाई है। लेकिन का नूतन मंत्री को इस विषय पर सदन में आकर जानकारी देनी चाहिए। तुणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि मामले से जुड़े जज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रान्सफर करना ठीक नहीं है। क्योंकि इलाहाबाद और कोलकाता हाईकोर्ट कोई डिपिंग वाउचर नहीं है कि जहां पर श्रद्धे जजों की भेज दिया जाए।

सांगा के अपमान पर उदयपुर में विरोध, ज़ापन

एजेसी ►► उदयपुर

उत्तर प्रदेश के सपा सांसद रामजी लाल के महाराणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद से राजस्थान समेत देश भर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को करणी सेना के अर्जुन सिंह चुंडावत के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम एक ज़ापन भी सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद रामजी लाल के बयान को गलत बताया और उन पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अर्जुन सिंह चुंडावत ने एक बड़ा एलान भी किया। उन्होंने कहा कि जो सांसद रामजी लाल की जुबान काटकर लाएगा, उसे 5.51 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा।

विवाद के बीच करणी सेना ने किया बड़ा ऐलान

सपा सांसद की जुबान काटने वाले को देंगे 5.51 लाख रु. का इनाम



सम्मान से समझौता स्वीकार्य नहीं

उन्होंने कहा कि अगर सुमन ने शब्द वापस नहीं लिए और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो उठा आंदोलन किया जाएगा। चुंडावत ने कहा कि महाराणा सांगा न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे भारत के गौरव हैं, उनके सम्मान से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इतिहास से अनजान लोगों को इस तरह की टिप्पणियां करने से पहले सोचना चाहिए।

दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प, अब आ रही तेजी

किसानों से उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही उपज: शिवराज सिंह

तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। चौहान ने बताया कि कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 2028-29 तक अगले चार वर्षों के लिए राज्य के उत्पादन का 100 प्रतिशत तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद की जाएगी। खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में तुअर (अरहर) की खरीद को मंजूरी दी है। इसके

साथ ही किसानों के हित में कर्नाटक में खरीद अवधि को 90 दिनों से आगे 30 दिन बढ़ाकर 1 मई तक करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है और 25 मार्च 2025 तक इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर (अरहर) की खरीद की गई है जिससे इन राज्यों के 1,71,569 किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में तुअर की कीमत वर्तमान में एमएसपी से ऊपर चल रही है। चौहान ने बताया कि भारत सरकार केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से किसानों से 100 प्रतिशत तुअर की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। इसी तरह, आरएमएस 2025 के दौरान चना, सरसो और मसूर की खरीद को मंजूरी दी गई है। पीएम-आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाया गया है। इसके तहत किसानों से एमएसपी पर दालों और तिलहन की खरीद जारी रहेगी। आरएमएस 2025 के लिए चने की कुल स्वीकृत मात्रा 27.99 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 28.28 लाख मीट्रिक टन है। प्रमुख राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। मसूर की कुल स्वीकृत मात्रा 9.40 लाख मीट्रिक टन है।



खबर संक्षेप

चिली के राष्ट्रपति बोरिक फॉन्ट आएंगे भारत

नई दिल्ली। चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट पीएम मोदी के निमंत्रण पर 1-5 अप्रैल तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे।

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह ऐलान किया। बोरिक के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा, जिसमें मंत्री, संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापार संघ, मीडिया और भारत-चिली सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े प्रमुख चिलीवासी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के रूप में यह बोरिक की पहली भारत यात्रा होगी। वह 5 अप्रैल को चिली लौटने से पहले आगरा, मुंबई और बंगलुरु भी जाएंगे। यात्रा के दौरान, बोरिक 1 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें भारत-चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी।

पीएम मोदी के ‘स्वस्थ भारत मिशन’ का विश्व में बजा डंका

एजेंसी ►► नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी के ‘स्वस्थ भारत मिशन’ के तहत देश भर में चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से देश में व्यापक पैमाने पर बदलाव आया है। पूरी दुनिया इस योजना का लोहा मान रही है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के तहत शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की तारीफ की है। इतना ही नहीं यूएन ने पीएम मोदी की आयुष्मान भारत योजना को भी शानदार बताया है। एक कार्यक्रम के दौरान यूएन ने ‘आयुष्मान भारत’ जैसी स्वास्थ्य पहलों का उदाहरण देते हुए शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भारत के प्रयासों और प्रगति की सराहना की तथा इसे ‘अनुकरणीय’ बताया। यूएन ने कहा कि देश ने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बचाया है। मंगलवार को जारी संयुक्त राष्ट्र के एक समूह की शिशु मृत्यु दर आकलन रिपोर्ट में भारत, नेपाल, सेनेगल, घाना और बुर्ंडी का उदाहरण दिया गया तथा शिशु मृत्यु दर रोकने में हुई प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाली विभिन्न रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन देशों ने दिखाया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, साक्ष्य-आधारित रणनीतियों और निरंतर निवेश से मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है।

यूएन ने आयुष्मान योजना और शिशु मृत्यु दर में कमी को बताया अनुकरणीय, राजनीतिक इच्छाशक्ति व निवेश से मिली सफलता

भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि देश ने स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया है। अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से भारत में लाखों लोगों का जीवन बचा चुका है और लाखों लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया है

■ भारत की आयुष्मान को बताया दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना

■ भारत ने स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश से लोगों का जीवन बचाया



शिशुओं की मृत्यु में 61 फीसदी की आई कमी

भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि देश ने स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया है। इसमें कहा गया कि अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से भारत पहले ही लाखों लोगों का जीवन बचा चुका है और लाखों अन्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रकाश डाला गया कि वर्ष 2000 से भारत ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70 प्रतिशत की कमी तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 61 प्रतिशत की कमी हासिल की है।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने की रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा की पुष्टि

यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की यात्रा करेंगे पुतिन, रूस में तैयारियां जोरों पर

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

यूक्रेन के साथ कुल करीब तीन साल से अधिक समय से भीषण जंग में उलझे हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे। इसके लिए उन्होंने भारत के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अब रूस में उनकी इस यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यह जानकारी गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी। उन्होंने हालांकि इस यात्रा से जुड़ी हुई कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है। लेकिन यह कहा कि पिछले साल 2024 में चुनाव जीतने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए रूस को चुना था और अब हमारी बारी है। यहां बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच यह पहला मौका होगा जब रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा करेंगे। लावरोव रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास से बातचीत कर रहे थे। उस दौरान ही उन्होंने रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बारे में बताया।

मोदी-पुतिन वार्ता में उठेंगे यह मुद्दे

आईआरआईजीसी की बैठक में दोनों शीर्ष नेताओं के बीच भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मामलों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौती के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति का मसला भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की वार्ता में शामिल किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। जंग के मैदान में युद्ध की समाप्ति पर बातचीत नहीं की जा सकती है। यूक्रेन युद्ध में भारत की अभी तक की भूमिका तटस्थ देश की ही रही है। लेकिन उसने लगातार बातचीत और कूटनीति से इसका समाधान निकालने पर जोर दिया है।

इजराइल में नए राजदूत सिंह के सम्मान में दिखाई जाएगी ‘द डिप्लोमैट’ फिल्म तेल अविव। इजराइल में भारत के नए राजदूत जेपी सिंह के स्वागत में वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से फिल्म ‘द डिप्लोमैट’ दिखाई जाएगी। ये फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है। फिल्म जेपी सिंह पर ही बनी है। यह पहल इजराइल में भारत के नए राजदूत का गर्मजोशी से स्वागत करने और दोनों देशों के बीच ‘मजबूत रिश्ते’ बनाने के लिए है। इजराइली विदेश मंत्रालय के सांस्कृतिक प्रभाग के प्रमुख नूरित तिनारी ने बताया कि यह फिल्म भारतीय कूटनीति की ताकत का जश्न मनाती है। फिल्म की स्क्रीनिंग एक ऐतिहासिक घटना होगी।

जापान के प्रतिनिधिमंडल से मिले पीएम दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर हुई विस्तृत चर्चा



एजेंसी ►► नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान कॉर्पोरेट कार्यकारी संघ के अध्यक्ष ताकेशी निनामी के नेतृत्व वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए उनके विचारों और सुझावों को सुना। इस चर्चा में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करना, निवेश के

भारत का शासन नीति संचालित

पीएम मोदी ने भारत में जापानी निवेश को सुविधाजनक बनाने और तेजी लाने के लिए भारत में विकसित जापान प्लस प्रणाली पर भी चर्चा की। इस बात पर भी जोर दिया कि निवेशकों के लिए कोई अपघटन या हिचकियाहट नहीं होनी चाहिए। भारत का शासन नीति संचालित है और सरकार पारदर्शी और पूर्वावगमित शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने देश में विमानन क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत नए हवाई अड्डों के निर्माण और रस्द क्षमताओं के विस्तार सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहा है।

श्रीलंकाई नौसेना ने 11 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार



एजेंसी ►► कोलंबो

श्रीलंकाई नौसेना ने गुरुवार को विशेष अभियान के तहत उत्तरी क्षेत्र में डेल्टा द्वीप के समीप 11 भारतीय मछुआरों को कथित रूप से अपने जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया और उनकी टॉलर को जब्त कर लिया। गिरफ्तार किए गए मछुआरों को कांकासनथुराई बंदरगाह लाया गया है, जहां उन्हें आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए मिलादी के मत्स्य निरीक्षक को सौंपा जाएगा।

पाक जेल में भारतीय मछुआरे की मौत

कराची। पाकिस्तान के कराची की मसीर जेल में बंद 52 वर्षीय मछुआरे की मौत हो गई। उसने कथित तौर पर अपनी कोठरी में आत्महत्या कर ली। मछुआरे का शव बैरक के शौचालय में रखी से लटका मिला। वह फरवरी 2022 से जेल में बंद था। जेल अधीक्षक अरशद हुसेन ने बताया कि मौत राम आनंद ने मंगलवार रात बैरक के शौचालय में रखी से फांसी लगा ली। उन्होंने बताया कि आनंद को जेल के डॉक्टरों ने रात करीब 2:30 बजे मृत घोषित कर दिया। आनंद के शव को इंदी ट्रस्ट के शवगृह भेज दिया गया है, जहां औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

युवाओं को संबोधित करते हुए बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत, आशावादी समाज और तकनीक अपनाने में अग्रणी, ऐसा दुनिया में नहीं

एजेंसी ►► नई दिल्ली

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू भवन में सेंट्रल एशिया यूथ डेलिगेशन को संबोधित किया। उन्होंने भारत के आशावादी दृष्टिकोण और देश के युवाओं द्वारा तकनीक को तेजी से अपनाने को प्रमुख विशेषता बताया। उन्होंने कहा कि आज, हम एक बहुत ही आशावादी समाज हैं। अगर आप भारत के युवाओं से पूछेंगे, तो उन्हें लगता है कि उनका जीवन बेहतर होगा।

एआई फ़ैंडली तकनीक

उन्होंने कहा कि देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) फ़ैंडली बनाने के लिए तकनीकों को अपनाने की मानसिकता विकसित करनी होगी। एशिया सोसायटी के क्यूंग-व्हा कांग के साथ बातचीत में भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की। कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर खुली बातचीत होती है। साल के अंत तक एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमत हुए हैं।



युवा नई तकनीक अपना रहे जयशंकर ने भारत के इस सकारात्मक दृष्टिकोण को तुलना वैश्विक स्थिति से करते हुए कहा कि दुनिया के हर हिस्से में ऐसा आत्मविश्वास नहीं है। उन्होंने भारतीय युवाओं में तकनीक अपनाने की प्रवृत्ति को भी उजागर किया।

लाल सागर में पर्यटन पनडुब्बी डूबने से हुआ बड़ा हादसा 40 में से 6 की मौके पर ही मौत, 14 घायल, 4 की हालत गंभीर

एजेंसी ►► काहिरा

मिस्र के हर्गड़ा शहर के पास लाल सागर में एक पर्यटन पनडुब्बी डूबने से बड़ा हादसा हो गया। घटना में छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 रूस के नागरिक और 2 मिस्र के थे। जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के वक्त पनडुब्बी में करीब 40 यात्री सवार थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, गुरुवार सुबह यह दुर्घटना हुई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बचाव दल ने अब तक 29 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हालांकि, अभी तक इस हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी खराबी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या समुद्र की प्रतिकूल परिस्थितियां इस दुर्घटना की वजह हो सकती हैं।



29 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला

हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं

पिछले साल भी हुआ था हादसा

हर्गड़ा मिस्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी खूबसूरत समुद्री तटरेखाओं और कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है। टूरिस्टों को समुद्र के अंदर का अनुभव देने के लिए यहां कई तरह की नौकाएं और पनडुब्बियां चलाई जाती हैं। हाल के सालों में इस क्षेत्र में पर्यटक नौकाओं से जुड़े कई हादसे सामने आए हैं। इससे पहले, पिछले साल नवंबर में ‘सी स्टोरी’ नाम की एक टूरिस्ट बोट डूब गई थी, जिसमें 11 लोग मारे गए थे या लापता हो गए थे, जबकि 35 लोगों को बचा लिया गया था।

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

हर्गड़ा और रेड सी तट पर टूरिस्टों की संख्या ज्यादा होने के कारण इन हादसों को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार पर अब दबाव बढ़ रहा है कि वह टूरिस्ट पनडुब्बियों की सुरक्षा जांच को और कड़ा करे। इस दुर्घटना के बाद रेड सी में चल रही अन्य टूरिस्ट पनडुब्बियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं।

ट्रंप का विदेश में बने वाहनों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान

साझेदारों के साथ बढ़ेगा तनाव, कार की कीमतों और नौकरियों पर पड़ेगा असर

एजेंसी ►► वॉशिंगटन



अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऑटो आयात पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इस फैसले अमेरिका का व्यापारिक साझेदारों के साथ तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, हम अमेरिका के बाहर बनी कारों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अगर कार अमेरिका में बनी है, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यह टैरिफ दो अप्रैल से लागू होंगे और विदेश में बनी कारों व हल्के ट्रकों पर असर डालेगा। यह मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होगा। ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर के मुताबिक, अमेरिकी टैरिफ कारों की कीमत को हजारों डॉलर तक बढ़ा सकता है।

कनाडाई पीएम बोले- यह हमारे देश पर सीधा हमला

टोरंटो। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऑटोमोबाइल आयात पर 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा को अपने देश पर ‘सीधा हमला’ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह व्यापार युद्ध न केवल कनाडा, बल्कि खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के उपभोक्ताओं को भरोसा कई वर्षों के निम्नतम स्तर पर है।